crops worth Rs. 4.5 crores besides causing deaths of a number of people;

(b) whether in a large number of villages, mango orchards and paddy fields were damaged;

(c) if so, whether the Central Government have provided help and assistance to the people affected by the hailstorm;

(d) whether in June, 1996 heavy rains and hailstorm killed 89 people and damaged property worth crores of rupees; and

(e) if so, the help and assistance provided by the Central Government?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (e) According to information received from the Government of Andhra Pradesh, hailstorms during March-April, 1996 had affected agricultural and horticultural crops in an area of 35865 hectares and resulting in loss of 9 human lives. The cyclone and heavy rains of June, 1996 killed 100 people and damaged property worth Rs. 129.00 crores.

Under the existing scheme for financing relief expenditure, the Stale Government undertakes necessary relief measures using the corpus of the Calamity Relief Fund. Two instalments of Central share of Calamity Relief Fund for 1996-97 amounting to Rs. 46.57 crores have been released to the Government of Andhra Pradesh to enable the State Government to undertake necessary relief measures.

कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश कम होना

*31. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1991-92 से कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश बहुत कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश की मात्रा में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) कृषि में सकल सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश 1980-81 के मूल्यों पर 1991-92 में 1002 करोड़ रुपये, 1992-93 में 1060 करोड़ रुपये तथा 1993-94 में 1178 करोड़ रुपये था। सरकारी तौर पर लगाये गये अनुमानों के अनुसार 1994-95 में सकल निवेश थोड़ा ही कम 1095 करोड़ रुपये था। ये निवेश 1980-81 की तुलना में बहुत कम हैं जबकि यह लगभग 1800 करोड़ रुपये था।

(ख) कृषि में निवेश में वृद्धि की धीमी गति का मुख्य कारण उर्वरक सिंचाई और बिजली आदि पर राज सहायता में वृद्धि होना है। इससे संबंधित विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है **(नीचे देखिए)**।

(ग) आठवीं योजना (1992—97) के तहत बागवानी, मात्स्यिकी, वर्षा सिंचित खेती, लघु सिंचाई तथा फसल कटाई उपरान्त प्रबंध के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन, जैसे कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त मात्रा में निवेश किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। कृषि के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के अधीन एक नया ग्रामीण बुनियादी विकास फंड स्थापित किया गया है। तथापि, गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा कृषि में निवेश लगातार बढ़ रहा है संलग्न विवरण II में इससे संबंधित विवरण दिया गया है।

विवरण-I

कृषि पर राजसहायता का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

मद	1980-81	1985-86	1990-91	91-92	92-93	93-94	94-95 (सं०प्रा०)	95-96 (ब,प्रा०)
उर्वरक पर राजसहायता	505	1924	4389	5185	6136	5194	5697	5900
बिजली पर राजसहायलता*	115	125	725	5938	7205	8888	*0113 (पू०वा०)	11178 (वा०यो०)

मद	1980-81	1985-86	1990-91	91-92	92-93	93-94	94-95 (सं०प्रा०)	95-96 (ब,प्रा०)
सिंचाई पर राजसहायलता**	903	1852	3791	4630	5214	5579	उ०न०	उ०न०

नोट: ब०प्रा०-बजट प्राक्कलन, सं०प्रा०-संशोधित प्राक्कलन, अ-अनन्तिम, उ०न०-उपलब्ध पू०वा०-पूर्व वास्तविक, वा०या०-वार्षिक योजना प्रक्षेपण

*सी०एस०ओ० के आंकड़े के आधार पर 1990-91 तक बिजली पर राज सहायता सभी विद्युत बोर्डों और निगमों के लिए समग्र राजसहायता है। 1991-92 से आगे, यह आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर केवल कृषि क्षेत्र से संबंधित है।

**नीति गत मामले के तौर पर किसानों को दिए जाने वाले पानी की आपूर्ति के लिए दरें कम रखी जाती है जिसका परिणाम यह है कि सरकारी सिंचाई प्रणाली को हानि होती है। सकल राजस्व की तुलना में प्रचालन लागत की अधिकता को इम्प्युटेड सिंचाई राजसहायता समझा जाता है।

विवरण-II

कृषि (1980-81 के मूल्य) में सकल पूंजी निर्माण

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	योग	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	प्रतिशत	
				कालम 2 का कालम 3	कालम 3 का कालम 4
1970-71	2758	789	1968	29.6	71.9
1980-81	4636	1796	2840	38.7	61.3
1990-91	4594	1153	3441	25.1	74.9
1991-92	4729	1002	3727	21.2	78.8
1992-93	5371	1060	4311	19.7	80.3
1993-94	5586	1178	4408	21.1	78.9
1994-95(त)	5857	1095	4762	18.7	81.3

त०-तत्काल अनुमान

स्रोत-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

Privatisation of ONGC Oilfields

*32. SHRI SANJAY DALMIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have decided to privatise some proven oilfields of ONGC; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) and (b) Government of India has so far made two offers to private companies for development of discovered small and medium sized oil fields in the year 1992 and 1993.

Under the first offer made in 1992, 31 small sized fields (28 of ONGC and 3 of OIL) and 12 medium sized fields (6 of ONGC and 6 OIL) were offered to private companies for development. Contracts have been signed for development of 13 small sized fields (all of ONGC) and 5 medium sized fields (4 of ONGC and one of OIL) under this offer.